प्रस्ताव
20 इस समय गैर-हिंसक माने जाने वाले कुछ अपराधों के लिए पैरोल को प्रतिबंधित करता है। वर्तमान में केवल छोटे अपराध माने जाने वाले कुछ अपराधों के लिए बड़े अपराध के दंड को अधिकृत करता है। पहल संबंधी कानून।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश महान्यायवादी द्वारा तैयार किया गया

इस उपाय के टेक्स्ट को राज्य सचिव की वेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर देखा जा सकता है।

- कुछ अपराधों के लिए पात्रता हटाकर अपने मूल अपराध के लिए पूरी कैद की अवधि को पूरा करने वाले गैर-हिंसक अपराधियों के लिए निर्धारित पैरोल कार्यक्रम की सुलभता को सीमित करता है।
- इस कार्यक्रम के तहत पैरोल निर्णयों को नियंत्रित करने वाले मानकों और आवश्यकताओं को बदलता है।
- कुछ ऐसे चोरी संबंधी अपराध जहाँ मूल्य $250 और $950 के बीच हो, सहित निर्दिष्ट चोरी संबंधी अपराधों के लिए बड़े अपराधों के प्रभार को अधिकृत करता है जिनसे इस समय छोटे अपराध के तौर पर प्रभार वसूला जाता है।
- निर्दिष्ट छोटे अपराधों के लिए अपराधी घोषित व्यक्तियों के लिए आवश्यक बनाता है कि वे राज्य डेटाबेस के लिए DNA नमूनों का संग्रह जमा करवाएं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मुख्यतः काउंटी की जेलों में कैदियों की संख्या और सामुदायिक पर्यवेक्षण के स्तर में वृद्धि होने के कारण प्रति वर्ष संभवतः दसियों मिलियन डॉलरों की बढ़ी हुई राज्य और स्थानीय सुधारक लागतें।
- बढ़ी हुईं राज्य और स्थानीय अदालत संबंधी लागतें जो कि वार्षिक रूप से कई मिलियन डॉलरों से अधिक हो सकती हैं।
- DNA नमूनों को एकत्र और संसाधित करने से संबंधित बढ़ी हुई राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन लागतें जिनके वार्षिक रूप से कुछेक मिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना नहीं है।

20

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

समीक्षा

प्रस्ताव 20 में चार मुख्य प्रावधान हैं। यह:

- चोरी से संबंधित कुछ अपराधों के लिए आपराधिक जुर्मानों को बढ़ाने के लिए राज्य के कानून में परिवर्तन करता है।
- राज्य के कारागार से रिहा किए गए लोगों का समुदाय में पर्यवेक्षण कैसे किया जाता है, इसमें परिवर्तन करता है।
- कारागार से कैदियों की रिहाई पर विचार करने के लिए प्रस्ताव 57 (2016) द्वारा बनाई गई प्रक्रिया में अनेक बदलाव करता है।
- राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए कुछ अपराधों के दोषी बालिग व्यक्तियों के DNA एकत्र करने को आवश्यक बनाता है।

नीचे, हम इन प्रमुख प्रावधानों में से प्रत्येक पर चर्चा करते हैं और प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का वर्णन करते हैं।

चोरी से संबंधित कुछ अपराधों के लिए आपराधिक दंड

पृष्ठभूमि

घोर अपराध सबसे गंभीर प्रकार का अपराध है। राज्य कानून कुछ घोर अपराधों को "हिंसक" या "गंभीर" या दोनों के तौर पर परिभाषित करता है। हिंसक और गंभीर के तौर पर निर्धारित घोर अपराधों के उदाहरणों में हत्या, डकैती और बलात्कार शामिल हैं। घोर अपराधों के तौर पर निर्धारित जिन्हे हिंसक या गंभीर नहीं माना जाता उनके उदाहरण मानव तस्करी और नशीले-पदार्थ बेचना है। दुष्कर्म

कम गंभीर अपराध है। दुष्कर्म में मारपीट और सार्वजनिक स्थानों पर नशे में रहने जैसे अपराध सम्मिलित हैं।

घोर अपराधों के लिए सज़ा। घोर अपराधों के दोषी लोगों को निम्न प्रकार की सज़ा दी जा सकती है:

- ***राज्य का कारागार।*** ऐसे लोग जिनकी वर्तमान या पिछली सज़ाओं में गंभीर, हिंसक या यौन अपराध शामिल हैं, उन्हें राज्य के कारागार में सज़ा हो सकती है।
- ***काउंटी जेल और/या सामुदायिक पर्यवेक्षण।*** जिन लोगों को गंभीर, हिंसक या यौन अपराधों के लिए वर्तमान में या अतीत में कोई सज़ा नहीं हुई है, उन्हें आमतौर पर काउंटी जेल की सज़ा सुनाई जाती है या समुदाय में काउंटी प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है या दोनों होते हैं।

दुष्कर्म के लिए सज़ा। दुष्कर्म के दोषी लोगों को काउंटी जेल, काउंटी समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण, जुर्माना या तीनों के कुछ संयोजन की सज़ा सुनाई जा सकती है। उन्हें आम तौर पर घोर अपराधों के दोषी लोगों से कम सज़ा दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक दुष्कर्म की सज़ा जेल में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, जबकि घोर अपराधों के लिए जेल या कारागार में अधिक समय तक सज़ा काटना आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा, दुष्कर्म के दोषी लोगों का आमतौर पर कम वर्षों के लिए समुदाय में पर्यवेक्षण किया जाता है और प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा करीब से पर्यवेक्षण नहीं भी किया जाता है।

सज़ा की वॉबलर (डगमगाती हुई) स्थिति। वर्तमान में, कुछ अपराधों जैसे कि पहचान की चोरी को घोर अपराध या दुष्कर्म के तौर पर दंडित किया जा सकता है। इन अपराधों को ‘‘वॉबलर (डगमगाते हुए) अपराधों’’ के तौर पर जाना जाता है। निर्णय सामान्य तौर पर अपराध की सम्पूर्ण जानकारी और किसी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास पर आधारित होता है।

प्रस्ताव 47 कुछ अपराधों के लिए दंडों को कम कर करता है। नवंबर 2014 में, मतदाताओं ने प्रस्ताव 47 को मंजूरी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप चोरी से संबंधित कुछ अपराधों के लिए घोर अपराधों की बजाय दुष्कर्मों के तौर पर सज़ा दी गई। उदाहरण के लिए, प्रस्ताव 47 के तहत, $950 या उससे कम की संपत्ति से संबंधित चोरी को सामान्य तौर पर छोटी चोरी माना जाता है और उसके लिए एक दुष्कर्म के तौर पर सज़ा दी जाती है — बजाय कि गोर अपराध के तौर पर जैसा कि पहले कभी-कभार संभव था (जैसे कि यदि कार चोरी की गई हो)। प्रस्ताव 47 में आम तौर पर यह भी आवश्यक होता है कि $950 या उससे कम की चोरी को एक दुष्कर्म के तौर पर दंडित किया जाए, न कि — घोर अपराध के तौर पर जैसा कि पहले संभव था।

प्रस्ताव

चोरी से संबंधित कुछ अपराधों के लिए दंडों में वृद्धि करता है प्रस्ताव 20 चोरी से संबंधित दो नए अपराधों को निर्मित करता है:

- ***बार-बार की जाने वाली चोरी।*** अतीत के चोरी से संबंधित अपराधों (जैसे सेंधमारी, जालसाजी या कार जैकिंग) के लिए दो या दो से अधिक बार दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति, जिसे उठाईगिरी या $250 से अधिक की संपत्ति की चोरी का दोषी पाया गया हो, उसे बार-बार की जाने वाली चोरी की सज़ा दी जा सकती है।
- ***संगठित रिटेल चोरी।*** कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, जो दो या दो से अधिक बार चोरी या उठाईगिरी करता है और जहां 180 दिनों के भीतर चुराई गई संपत्ति का कुल मूल्य $250 डॉलर से अधिक हो जाता है तो उसे संगठित रिटेल चोरी का आरोपी ठहराया जा सकता है।

ये दोनों नए अपराध वॉबलर अपराध होंगे, जिनके लिए काउंटी जेल में तीन साल तक की सज़ा हो सकती है, भले ही अतीत में उस व्यक्ति को गंभीर, हिंसक या यौन अपराधों का दोषी ठहराया गया हो।

इसके अलावा, प्रस्ताव 20 चोरी से संबंधित कुछ मौजूदा अपराधों को जिन्हें सामान्य तौर पर प्रस्ताव 47 के तहत दुष्कर्म के तौर पर दंडित किया जाता है उन्हें घोर अपराध के तौर पर दंडित किए जाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, मौजूदा कानून के तहत, किसी स्टोर से $950 डॉलर से कम की संपत्ति की सभी चोरियों के लिए आम तौर पर एक दुष्कर्म के तौर पर दंडित किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव 20 के तहत, जो लोग स्टोर से $950 से कम की संपत्ति चुराते हैं, जो किसी बिक्री (जैसे कि नकदी रजिस्टर) के लिए नहीं है, उन्हें घोर अपराध की सज़ा मिल सकती है। इससे इन अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों को दोषी ठहराए जाने की संख्या में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, काउंटी जेल में छह महीने तक की सज़ा की बजाय, वे काउंटी जेल या राज्य कारागार में तीन साल तक की सज़ा पा सकते हैं।

हमारा अनुमान है कि उपरोक्त बदलावों से प्रत्येक वर्ष कुछ हजार व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, यह अनुमान सीमित रूप में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या अभियोजकों और न्यायाधीशों के विकल्पों पर निर्भर करेगी। नतीजतन, वास्तविक संख्या बहुत अधिक या कम हो सकती है।

सामुदायिक पर्यवेक्षण कार्यप्रणालियाँ

पृष्ठभूमि

जो लोग गंभीर या हिंसक अपराध के लिए सज़ा की अवधि पूरी करने के बाद राज्य के कारागार से रिहा होते हैं उनका आमतौर पर समुदाय में कुछ समय के लिए राज्य पैरोल एजेंट द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। अन्य अपराधों के लिए सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा होने वाले लोगों का आमतौर पर काउंटी प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा समुदाय में पर्यवेक्षण किया जाता है - जिसे सामान्य तौर पर रिहा होने के बाद समुदाय में पर्यवेक्षण (Post-Release Community Supervision, PRCS) कहा जाता है। जब राज्य पैरोल या PRCS के तहत लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिनका उन्हें पालन करना आवश्यक होते है—जैसे "उनके पर्यवेक्षण के नियम" का उल्लंघन करना—तब स्टेट पैरोल एजेंट या काउंटी प्रोबेशन अधिकारी न्यायाधीश से उनके पर्यवेक्षण की शर्तों को बदलने के लिए कह सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कठोर शर्तें या काउंटी जेल में भेजा जा सकता है।

प्रस्ताव

सामुदायिक पर्यवेक्षण कार्यप्रणालियों को बदलता है। यह प्रस्ताव राज्य पैरोल और PRCS कार्यप्रणालियों में अनेक बदलाव करता है। उदाहरण के लिए, PRCS के तहत यदि लोग तीसरी बार पर्यवेक्षण के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रोबेशन अधिकारी न्यायाधीश से पर्यवेक्षण के नियमों को परिवर्तित करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा, यह प्रस्ताव राज्य पैरोल और काउंटी प्रोबेशन विभागों के लिए पर्यवेक्षण किए जाने वाले लोगों के बारे में अधिक जानकारी के आदान-प्रदान को आवश्यक बनाता है।

प्रस्ताव 57 रिहाई के लिए विचार किए जाने की प्रक्रिया

पृष्ठभूमि

जेल में बंद लोगों को प्राथमिक अपराध का दोषी ठहराया गया है। यह सामान्य तौर पर वैसे अपराध होते है जिसके लिए उन्हें जेल में सबसे अधिक समय बिताने की सज़ा मिलती है। वे अक्सर उनके केस के तथ्यों के कारण जेल में अतिरिक्त समय बिताते हैं (जैसे कि यदि उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल किया हो) या किसी अन्य के लिए, निम्न अपराध जिसके लिए उन्हें एक ही समय में दोषी ठहराया गया था। उदाहरण के लिए, पहले गंभीर या हिंसक अपराध के दोषी ठहराए गए लोगों को आम तौर पर किसी

भी नए घोर अपराध के लिए दोगुनी सज़ा पूरी करना आवश्यक बनाता है।

नवंबर 2016 में, मतदाताओं ने प्रस्ताव 57 को मंज़ूरी दी थी, जिसने अहिंसक घोर अपराध के लिए दोषी ठहराए गए जेल के कैदियों को उनके प्राथमिक गुनाह की सज़ा पूरी करने के बाद रिहाई का विचार करने के राज्य के संविधान को बदल दिया। राज्य बोर्ड की पैरोल सुनवाई (Board of Parole Hearings, BPH) द्वारा कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाता है। विशेष रूप से, BPH कर्मचारी यह निर्धारित करने के लिए कि कैदी को छोड़ा जाएगा या नहीं, कैदी की फ़ाइलों की विभिन्न जानकारी, जैसे कि आपराधिक इतिहास और जेल में व्यवहार की समीक्षा करता है। BPH अभियोजन पक्ष, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कैदी के बारे में पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत किन्हीं पत्रों पर भी विचार करता है। California का सुधार और पुनर्वास विभाग (California Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR) राज्य के साथ पंजीकृत पीड़ितों से संपर्क करके उन्हें सूचित करता है कि वे ऐसे पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जब तक BPH यह तय नहीं कर लेता कि कैदी से अकारण हिंसा का खतरा नहीं है तब तक कैदी को रिहा नहीं किया जाता है। यदि कैदी को रिहा नहीं किया जाता है, तो वह निर्णय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है। जिन कैदियों की रिहाई को अस्वीकृत कर दिया जाता है, अगले वर्ष उनकी रिहाई पर दोबारा विचार किया जाता है, हालांकि अक्सर वे अपनी सज़ा पूरी कर लेते हैं और उससे पहले ही रिहा हो जाते हैं। 2019 में BPH ने लगभग 4,600 कैदियों पर विचार किया और लगभग 860 (19 प्रतिशत) की रिहाई की स्वीकृति दी।

प्रस्ताव

प्रस्ताव 57 रिहाई के लिए विचार किए जाने की प्रक्रिया में बदलाव करता है प्रस्ताव 20, प्रस्ताव 57 के रिहाई के लिए विचार किए जाने की प्रक्रिया में विभिन्न बदलाव करता है। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

- कुछ कैदियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखता है— जैसे कि वे लोग जिन्हे किसी प्रकार की मारपीट और घरेलू हिंसा के लिए सज़ा सुनाई गई है।
- BPH का उन कैदियों की रिहाई को अस्वीकृत करना आवश्यक बनाता है, जिनसे पीड़ितों को हानि पहुँचाने वाले घोर अपराध का अनुचित जोखिम होता है, इसकी बजाय उनसे जिनसे केवल हिंसा का अनुचित जोखिम होता है।
- कैदियों को रिहा करना है या नही यह विचार करने के लिए, BPH को अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना आवश्यक बनाता है, जैसे कि अपने अपराधों के बारे में कैदियों के दृष्टिकोण।
- जिन कैदियों की रिहाई को अस्वीकृत किया गया था, उन पर BPH द्वारा पुनर्विचार किए जाने से पहले दो साल (एक साल की बजाय) का इंतजार करना आवश्यक बनाता है।
- अभियोजन पक्ष को BPH को रिहाई के निर्णय की एक और समीक्षा का अनुरोध करने की अनुमति देता है।
- CDCR के लिए पीड़ितों को राज्य के साथ पंजीकृत नहीं होने पर भी उन्हें समीक्षा के बारे में सूचित करने के लिए पीड़ितों का पता लगाने का प्रयास करने को आवश्यक बनाता है।

DNA एकत्र करना

पृष्ठभूमि

California में, (1) घोर अपराध के लिए गिरफ़्तार हुए, इल्ज़ाम लगाए गए या सज़ा प्राप्त वयस्कों; (2) घोर अपराध करने वाले युवक; और (3) यौन अपराधियों या आगजनी करने वालों के तौर पर पंजीकृत होने वाले लोगों को DNA का नमूना देना आवश्यक है। इन नमूनों को राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए California न्याय विभाग

20

(California Department of Justice, DOJ) को दिया जाता है। DOJ वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 100,000 DNA नमूने प्राप्त करता है। DOJ एक राज्यव्यापी DNA डेटाबेस में DNA प्रोफ़ाइल संग्रहीत करता है और उन्हें एक राष्ट्रीय डेटाबेस में सबमिट करता है। इन डेटाबेस का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन विभाग द्वारा अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए किया जाता है।

प्रस्ताव

DNA संग्रह करने का विस्तार करता है। यह प्रस्ताव राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए कुछ अपराधों के दोषी वयस्कों के DNA एकत्र करने को आवश्यक बनाता है। इन अपराधों में उठाईगिरी, जाली चेक बनाना और कुछ घरेलू हिंसा के अपराध शामिल हैं।

वित्तीय प्रभाव

इस प्रस्ताव का राज्य और स्थानीय सरकारों पर विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रभाव होंगे। हालांकि, नीचे चर्चा किए गए प्रभावों का सटीक आकार कई कारकों पर निर्भर करेगा। एक प्रमुख कारक अदालतों और अन्य लोगों (जैसे काउंटी प्रोबेशन विभागों और अभियोजकों) द्वारा लिए गए निर्णय होंगे कि प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाएगा। उदाहरण के लिए, प्रस्ताव राज्य संविधान को बदले बिना प्रस्ताव 57 के तहत रिहाई के लिए विचार किए जाने के लिए कुछ कैदियों की संवैधानिक योग्यता में बदलाव करना चाहता है। यदि प्रस्ताव को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो न्यायाधीश यह निर्णय दे सकता है कि कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए राज्य और स्थानीय सरकार पर वित्तीय प्रभावों के हमारे अनुमान यह मानते हैं कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हो गया है। कुल मिलाकर, राज्य की लागतों में अनुमानित वृद्धि राज्य के वर्तमान सामान्य निधि बजट के एक प्रतिशत से भी कम होने को दर्शाती है। (सामान्य सामान्य निधि राज्य का मुख्य परिचालन खाता होती है, जिसे शिक्षा, जेलों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है।)

राज्य और स्थानीय सुधारक लागतें। यह प्रस्ताव राज्य और स्थानीय सुधारक लागतों में तीन तरीकों से वृद्धि करेगा।

- सबसे पहले, चोरी से संबंधित अपराधों के लिए दंडों में वृद्धि, मुख्य रूप से काउंटी जेल की आबादी और कुछ लोगों के लिए सामुदायिक पर्यवेक्षण के स्तर को बढ़ाने से, सुधारक लागतों में वृद्धि करेगी।
- दूसरा, सामुदायिक पर्यवेक्षण कार्यप्रणालियों में बदलाव से विभिन्न तरीकों से राज्य और स्थानीय लागतों में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, जो लोग PRCS पर हैं और उनका तीसरी बार उल्लंघन करते हैं, उनके लिए काउंटी प्रोबेशन अधिकारियों का PRCS के तहत लोगों के पर्यवेक्षण की अवधि को बदलने की आवश्यकता जेल की आबादी को बढ़ा सकती है यदि इसके कारण अधिक लोगों को जेल में रखना पड़ता है।
- तीसरा, प्रस्ताव 57 के रिहाई पर विचार की प्रक्रिया में किए गए बदलाव जेल से रिहा कैदियों की संख्या को कम करके राज्य की लागतों में वृद्धि करेंगे और सामान्य रूप से प्रक्रिया की लागत में वृद्धि करेंगे।

हमारा अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष कई हजारों से अधिक लोग प्रस्ताव से प्रभावित होंगे। परिणामस्वरूप हमारा अनुमान है कि **राज्य और स्थानीय सुधारक लागतों में प्रतिवर्ष संभवत: दसियों मिलियन डॉलरों** की वृद्धि होगी। वास्तविक वृद्धि कई अनिश्चित कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कि प्रस्ताव से प्रभावित लोगों की विशिष्ट संख्या।

राज्य और स्थानीय न्यायालय-संबंधित लागतें। प्रस्ताव राज्य और स्थानीय न्यायालय-संबंधित लागतों में वृद्धि करेगा। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों को चोरी से संबंधित अपराधों के लिए दुष्कर्मों के बजाय घोर अपराध के लिए सज़ा दी जाएगी। क्योंकि अदालतों को दुष्कर्म करने वालों की तुलना में घोर अपराध करने वालों को संभालने में अधिक समय लगता है, इसलिए अदालतों, काउंटी अभियोजकों और जनता के संरक्षकों और काउंटी शेरिफ़ (जो अदालत को सुरक्षा प्रदान करते हैं) के लिए काम के भार में वृद्धि होगी। इसके अलावा, PRCS के तहत लोगों द्वारा तीसरे उल्लंघन के बाद प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा उनकी पर्यवेक्षण की अवधि को बदलने के लिए न्यायाधीशों की अनुमति की आवश्यकता के परिणामस्वरूप अदालत पर अतिरिक्त कार्यभार होगा। हमारा अनुमान है कि प्रस्ताव से प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या के आधार पर, **अदालत से संबंधित यह लागतें सालाना कई मिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है**।

राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन लागतें। प्रस्ताव, DNA नमूने प्रदान करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या को बढ़ाकर राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन की लागतों में संभवत: सालाना दसियों हजार की संख्या में वृद्धि करेगा। हमारा अनुमान है कि **राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन की लागतों में संभवतः कुछ मिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि नहीं होगी**।

अन्य वित्तीय प्रभाव। प्रस्ताव के कारण राज्य और स्थानीय सरकारों पर अन्य अज्ञात वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दंडों में वृद्धि होने से अपराध में कमी आती है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली की कुछ लागतों से बचा जा सकता है। यह या अन्य प्रभाव किस हद तक घटित होंगे यह अज्ञात है।

प्रमुख रूप से इस उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए बनाई गई समितियों की सूची के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/* पर जाएं।

समिति के शीर्षस्थ 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर जाएं।

यदि आप इस राज्य के उपाय के संपूर्ण टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो कृपया राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें या आप *vigfeedback@sos.ca.gov* पर ईमेल भेज सकते हैं और आपको एक प्रतिलिपि नि:शुल्क डाक द्वारा भेज दी जाएगी।